



डज़ाइन कानून संधि(DLT)

प्रलिमिंस कर लयि:

[वशिव बौद्धकि संपदा संगठन \(WIPO\)](#), [डज़ाइन कानून संधि\(DLT\)](#), [औद्योगिक डज़ाइन](#), [बौद्धकि संपदा](#), [डज़ाइन अधनियिम, 2000](#), [ट्रपिस समझौता](#), [ट्रेडमार्क](#), [कॉपीराइट अधनियिम, 1957](#) ।

मुख्य परीक्षा के लयि:

बौद्धकि संपदा अधिकारों की सुरक्षा ।

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सहति [वशिव बौद्धकि संपदा संगठन \(WIPO\)](#) के सदस्य देशों ने [सऊदी अरब के रयाद](#) में आयोजति डज़ाइन कानून संधि को संपन्न करने और अपनाने के लयि राजनयकि सम्मेलन में [डज़ाइन कानून संधि\(डीएलटी\)](#) को अपनाया ।

भारत की बौद्धकि संपदा की स्थति

- भारत की नवाचार रैंकगि: WIPO के [वैश्वकि नवाचार सूचकांक \(GII\) 2024](#) में भारत को 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वाँ स्थान प्राप्त हुआ है ।
 - मध्य और दक्षिणी एशया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत प्रथम स्थान पर रहा है ।
- भारत की वैश्वकि IP रैंकगि: भारत सभी तीन प्रमुख बौद्धकि संपदा अधिकारों- [पेटेंट](#), [ट्रेडमार्क](#) और [औद्योगिक डज़ाइन](#) के लयि वैश्वकि शीर्ष 10 में स्थान पर है ।
 - वर्ष 2023 में 64,480 पेटेंट आवेदनों के साथ भारत वशिव स्तर पर छठे स्थान पर है ।
 - भारत का ट्रेडमार्क कार्यालय वशिव में सक्रयि पंजीकरणों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या रखता है, जसिमें 3.2 मिलियन से अधिक ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं ।
 - भारत के औद्योगिक डज़ाइन अनुप्रयोगों में वर्ष 2023 में 36.4% की वृद्धि होगी ।
- IP गतिविधि में वृद्धि: भारत का [पेटेंट- जीडीपी अनुपात](#) पछिले दशक में 144 से बढ़कर 381 हो गया है, जो आर्थकि विकास के अनुरूप IP गतिविधि के वसितार को दर्शाता है ।
 - पेटेंट-जीडीपी अनुपात पेटेंट गतिविधि के आर्थकि प्रभाव का एक माप है ।

डज़ाइन कानून संधि(DLT) क्या है?

- DLT के बारे में: DLT को वशिव में औद्योगिक डज़ाइन की सुरक्षा को सुव्यवस्थति और सुवधाजनक बनाने के लयि एक व्यापक ढाँचे के रूप में प्रस्तावति कया गया है ।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य लालफीताशाही को दूर करने तथा डज़ाइनरों के लयि अपनी बौद्धकि संपदा की सुरक्षा हेतु एक वशिवसनीय और आसानी से संचालति होने योग्य प्रणाली स्थापति करना है ।

प्रमुख प्रावधान:

- डज़ाइन आवेदन प्रक्रयाओं को सुव्यवस्थति करना:
 - उपयोग: एक आवेदन में एकाधिक डज़ाइन की अनुमति प्रदान करता है, तथा मूल रूप से दाखलि करने की तिथि को सुरक्षति रखता है, भले ही कुछ अस्वीकार कर दयि जाएँ ।
 - स्पष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताएँ: सभी डज़ाइन अनुप्रयोगों के लयि एक समान, स्पष्ट दशा-नरिदेश स्थापति करता है ।

- प्रतनिधित्व में लचीलापन: आवेदक औद्योगिक संपत्ति कार्यालयों के समक्ष डज़ाइन प्रस्तुत करने के लिये विभिन्न प्रारूपों (चित्र, फोटो, वीडियो) का उपयोग कर सकते हैं।
- आवेदन करने की प्रक्रिया में सुधार:
 - दाखल संबंधी समय सीमा का सरलीकरण: आवेदक प्रारंभ में आवश्यक भागों को जमा करके दाखल करने की तथि सुरक्षित कर सकते हैं, बाद में संपूर्ण आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
 - सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिये अनुग्रह अवधि: छह या 12 महीने की अनुग्रह अवधि, दाखल करने से पहले प्रकट किये गए डज़ाइन की नवीनता की रक्षा करती है।
- पंजीकरण के बाद की प्रक्रिया और सुरक्षा:
 - प्रकाशन नयित्रण: आवेदक आवेदन दाखल करने के बाद छह महीने तक प्रकाशन को नयित्त्रति कर सकते हैं, जिससे गोपनीयता एवं प्रतसिपर्द्धात्मक लाभ सुनिश्चित होता है।
 - समय सीमा में चूक होने पर राहत उपाय: समय सीमा से चूकने वाले आवेदकों को राहत प्रदान की जाएगी, जिससे उनके अधिकारों का नुकसान रोका जा सकेगा।
 - अनुदान-पश्चात लेनदेन स्पष्ट: पंजीकरण-पश्चात प्रक्रियाएँ (जैसे, स्थानांतरण, लाइसेंसिंग) आसान प्रबंधन और प्रवर्तन के लिये स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएगी।
- द्वि-स्तरीय संरचना: संघ में अनुच्छेद (संघ के मुख्य प्रावधान) और नयिम (कार्यान्वयन को नयित्त्रति करने वाले नयिम) शामिल होंगे।
 - अनुबंधकारी पक्षों की सभा डज़ाइन कानून और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये नयिमों में संशोधन कर सकती है।

औद्योगिक डज़ाइन क्या है?

- परिचय: औद्योगिक डज़ाइन एक सजावटी प्रकृति की मौलिक रचना है, जिसे जब किसी उत्पाद में शामिल किया जाता है या उस पर लागू किया जाता है, तो वह उसे विशेष रूप प्रदान करता है।
 - ये विशेषताएँ इसके आकार, रेखाओं, रूपरेखा, वनियस, रंग, बनावट या सामग्री के कारण हो सकती हैं।
 - एक डज़ाइन त्रि-आयामी हो सकता है, जैसे किसी उत्पाद का आकार, या द्वि-आयामी हो सकता है, जैसे किसी वशिष्ट सतह पैटर्न में।
 - यह एक बौद्धिक संपदा (IP) है जो मानव मस्तिष्क की अमूर्त रचनाएँ हैं जिनका मूल्य है लेकिन वे भौतिक वस्तुएँ नहीं हैं।
- अनुप्रयोग: डज़ाइन को उत्पादों की एक वसितृ शृंखला पर लागू किया जाता है, जैसे पैकेजिंग, फर्नीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, हस्तशिल्प वस्तुएँ और आभूषण।



Emoji



Bench



Pediatric dosing syringe

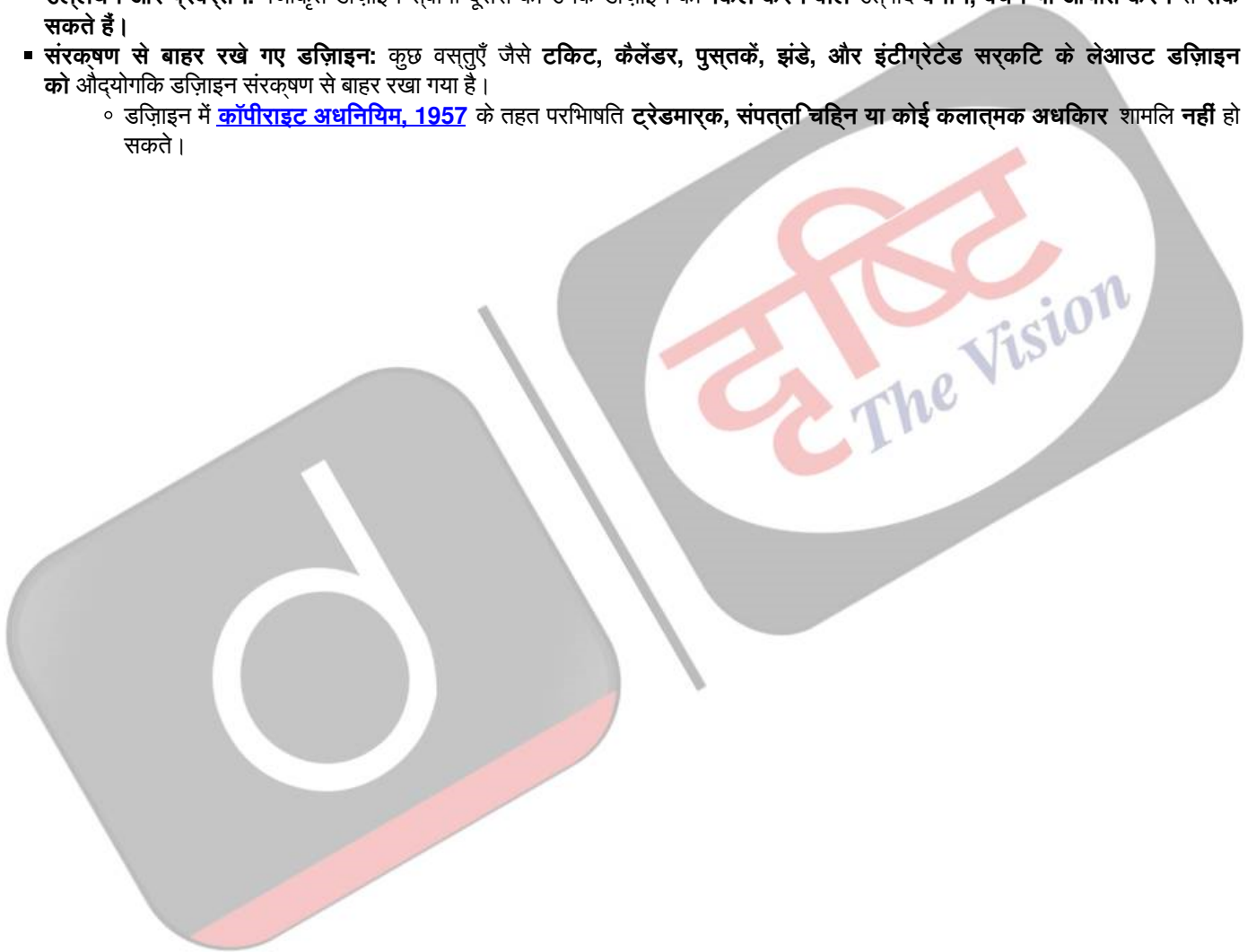
- महत्त्व: डज़ाइन व्यावसायिक परसिंपत्तियाँ हैं जो किसी उत्पाद के बाज़ार मूल्य को बढ़ा सकती हैं और प्रतसिपर्द्धात्मक लाभ प्रदान कर सकती हैं।
 - उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिये आकर्षक बनाकर, डज़ाइन उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करता है।
- संरक्षण: डज़ाइन को उस देश के बौद्धिक संपदा (IP) कार्यालय द्वारा नरिधारित फाइलिंग प्रक्रियाओं का पालन करना होगा जिसमें वे संरक्षण चाहते हैं।
 - डज़ाइन अधिकार प्रादेशिक होते हैं, अर्थात् किसी एक देश (या क्षेत्र) में प्राप्त संरक्षण से उत्पन्न अधिकार उस देश (या क्षेत्र) तक ही सीमित होते हैं।
 - भारत में औद्योगिक डज़ाइन को पंजीकरण और संरक्षण डज़ाइन अधिनियम, 2000 द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- भारत में औद्योगिक डज़ाइन: वर्ष 2014-24 के बीच भारत में डज़ाइन पंजीकरण में तीन गुना वृद्धि हुई, अकेले पछिले दो वर्षों में घरेलू पंजीकरण में 120% की वृद्धि हुई है।
 - उल्लेखनीय रूप से, वर्ष 2023 में डज़ाइन अनुप्रयोगों में 25% की वृद्धि हुई।

वशि्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

- परिचय: WIPO संयुक्त राष्ट्र की एक वशिष एजेंसी है जिसे वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और वशि्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये बनाया गया था।
- भूमिका: IP की सुरक्षा के लिये सेवाएँ प्रदान करना, IP से संबंधित मुद्दों के लिये मंच प्रदान करना, तथा वैश्विक नरिणय लेने में मार्गदर्शन के लिये डेटा और सूचना प्रदान करना।
- सदस्यता: इसके 193 सदस्य देश हैं। भारत वर्ष 1975 में WIPO में शामिल हुआ।

डज़ाइन अधनियिम, 2000 के अंतर्गत संरक्षण प्रावधान क्या हैं?

- पात्रता: यदडज़ाइन सौंदर्यपरक प्रकृतिके हैं और वस्तुओं पर लागू होते हैं तो उन्हें संरक्षति कयिा जाता है।
 - संरक्षण केवल वस्तु के सौंदर्य पर लागू होता है, उसके कार्यात्मक पहलुओं पर नहीं।
 - संरक्षण प्राप्त करने के लयि डज़ाइन को **डज़ाइन रजसिंटरी** में पंजीकृत होना चाहयि।
- सुरक्षा हेतु आवश्यकताएँ:
 - नवीनता और मौलिकता: डज़ाइन नया होना चाहयि और मौजूदा डज़ाइनों से काफ़ी अलग होना चाहयि।
 - अप्रकटीकरण: डज़ाइन का भारत या वदिश में सार्वजनकि रूप से प्रकटीकरण नहीं कयिा जाना चाहयि।
 - कार्यात्मक नहीं: कार्यात्मकता से प्रेरति डज़ाइन संरक्षति नहीं है।
 - आपत्तजनक नहीं: डज़ाइनों को सार्वजनकि नैतिकता, सुरक्षा, या अखंडता के साथ टकराव नहीं होना चाहयि।
- संरक्षण की अवधि: [ट्रपिस समझौते](#) के तहत संरक्षण कम से कम **10 वर्षों** तक रहता है जसिे नवीकरण आवेदन के माध्यम से अतिरिक्ति **5 वर्षों** के लयि बढ़ाया जा सकता है।
- उल्लंघन और प्रवर्तन: पंजीकृत डज़ाइन स्वामी दूसरों को उनके डज़ाइन की नकल करने वाले उत्पाद बनाने, बेचने या आयात करने से रोक सकते हैं।
- संरक्षण से बाहर रखे गए डज़ाइन: कुछ वस्तुएँ जैसे टकिट, कैलेंडर, पुस्तकें, झंडे, और इंटीग्रेटेड सर्कटि के लेआउट डज़ाइन को औद्योगकि डज़ाइन संरक्षण से बाहर रखा गया है।
 - डज़ाइन में [कॉपीराइट अधनियिम, 1957](#) के तहत परभिषति ट्रेडमार्क, संपत्ति चहिन या कोई कलात्मक अधिकार शामिल नहीं हो सकते।



बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।



IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।



संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):
 - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 (पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।
 - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 (कॉपीराइट)।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:
 - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
 - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:
 - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- मर्रिकेश VIP समझौता, 2016:
 - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को अनुच्छेद 27 (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।



भारत की पहल और IPR

- राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:
 - आदर्श वाक्य: "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
 - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
 - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
 - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन (NIPAM)
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम (KAPILA)

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल



बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार - नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक् करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष

औद्योगिक डिज़ाइन संबंधी नरिणय

- 2016: रतिकी (एक बुटीक परधान डिज़ाइनर) ने दल्लि उच्च न्यायालय में बीबा पर कपडों के पुनरुत्पादन एवं बकिरी के संदर्भ में मुकदमा दायर किया, जसिम रतिकी के डिज़ाइनों की नकल की गई थी जबकि ये डिज़ाइन, डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकृत नहीं थे।

प्रश्न: वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और वयापार गपतरियों के बीच मोटे तौर पर वभिदन कीजयिए। (2014)

